



राजपत्र, हिमाचल प्रदेश

(असाधारण)

हिमाचल प्रदेश राज्य शासन द्वारा प्रकाशित

शिमला, बोरवार, 27 जनवरी, 2000/7 माघ, 1921

हिमाचल प्रदेश सरकार

पंचायती राज विभाग
द्वारा
आदेश

शिमला-9, 31 दिसम्बर, 1999

संख्या पी० सी०एच०एच०ए० (5)98-99 पोले दा खाला-23475-83.—यह कि श्रीमती सुन्दरी देवी, प्रधान, ग्राम पंचायत पोले दा खाला, विकास खण्ड नालागढ़, जिला सोलन को उपायुक्त सोलन द्वारा उनके कार्यालय आदेश सं० एस०एल० एन०-4-118 (पंच)/87-3 358-63, दिनांक 21-9-1999 द्वारा निम्नलिखित आरोपों में संलिप्त पाए जाने के कारण प्रधान पद से निलम्बित किया गया :—

1. यह कि प्रधान, ग्राम पंचायत पोले दा खाला द्वारा माह दिसम्बर, 1997 से दिसम्बर, 1998 तक पंचायत मुख्यावास में कोई भी मासिक बैठक नहीं बुलाई गई।
2. यह कि सिंचाई टैंक काटली के निर्माण हेतु प्रधान द्वारा 50 बैग सिमेंट खरीदे गए जिसमें से सिर्फ 40 बैग प्रधान द्वारा उपयोग किए गए जब 10 बैग प्रधान द्वारा योजना पर उपयोग नहीं किए गए

मूल्य : 1 रुपया।

इस प्रकार प्रधान की 10 बैगों की कीमत 1370/- रु तथा ढुलाई 200/- रु कुल 1570/- रु का छलहरण में संलिप्तता पाई गई उपरोक्त के अतिरिक्त इसी योजना हेतु प्रधान द्वारा 4500 पत्थर खरीदे गए जिसमें से 3600 पत्थर ही प्रयोग में लाए गए। अतः 900 पत्थरों की, मु० 1080/- रु तुड़ाई तथा 675/- रु षड़ाई के, कुल 1755/- रु प्रधान द्वारा दुरुपयोग किया गया इसी योजना हेतु प्रधान द्वारा 400 फुट रेत खरीदा गया जिसमें से 300 फुट रेत ही प्रयोग में लाया गया। अतः 100 फुट रेत की कीमत मु० 400/- रु तथा ढुलाई रजवाई खड्ड से सिंचाई टैंक तक मु० 2000/- रु के छलहरण में प्रधान की संलिप्तता पाई गई। अतः प्रारम्भिक छानबीन के अनुसार 10 बैगों की कीमत व ढुलाई के मु० 1570/- रु, 900 पत्थरों की तुड़ाई व षड़ाई के मु० 1755/- रु तथा 100 फुट रेत की कीमत व ढुलाई के मु० 2400/- रु, कुल 5725/- रु के दुरुपयोग/छलहरण करने में प्रधान संलिप्तता पाई गई।

3. यह कि निर्माण पूर्वी खजुरन हेतु 40 बैग सिमेंट खरीदे गए जिसमें से स्टाक रजिस्टर अनुसार 10 बैग सिमेंट कम प्रयोग लिए गए। इसी योजना पर मु० 75/- रु 50 फुट गठका पत्थर तुड़ाई तथा 525/- रु 150 बजरी तुड़ाई का व्यय प्रधान द्वारा दर्शाया गया जबकि स्टाक रजिस्टर अनुसार गठका/बजरी तुड़ान इस स्कीम के मस्ट्रोल नं० 8 अवधि 15-5-97 से 21-5-97 के अन्तर्गत मजदूरों ने किया है। अतः प्रारम्भिक छानबीन के अनुसार 10 बैगों की कीमत व ढुलाई 1490/- रु और गठका पत्थर तुड़ाई व बजरी तुड़ाई मु० 600/- रु, कुल 2090/- रु के दुरुपयोग/छलहरण में प्रधान की संलिप्तता पाई गई।

4. निर्माण रिटैनिंग बाल क्ष्वारन हेतु प्रधान द्वारा 25 बैग सिमेंट खरीदे गए लेकिन उपयोग सिर्फ 15.5 बैग ही किए गए। शेष सिमेंट का प्रधान द्वारा निजी कार्य हेतु उपयोग किया गया। इसी योजना के लिए 13 बैग सिमेंट की खरीद, 142 रु प्रति बैग की दर से मु० 1846/- रु ढुलान 7 रु प्रति बैग मु० 91/- रु तथा गाड़ी किराया मु० 130/- रु तथा 150 फुट रेत की कीमत मु० 1500/- रु तथा रेत की ढुलाई मु० 7/- रु प्रति फुट का 1050/- रु का व्यय प्रधान द्वारा दर्शाया गया लेकिन व्यय रजिस्टर में उपयोग अन्य दर्शाया गया है। उपरोक्त अवधि सामान का विवरण निम्न प्रकार से है :-

10 बैग सिमेंट दर 137/- रु प्रति बैग	1370.00
गाड़ी किराया 12/- रु प्रति बैग	120.00
ढुलान मु० 7/- रु	70.00
13 बैग सिमेंट मु० 142 रु प्रति बैग	1845.00
13 बैग सिमेंट गाड़ी का किराया	130.00
ढुलान मु० 7/- रु प्रति बैग	91.00
150 बैग रेत का गाड़ी किराया	1500.00
ढुलान मु० 7/- रु प्रति बैग	1050.00
कुल	6176.00

अतः प्रारम्भिक छानबीन के अन्तर्गत उपरोक्त प्रधान ग्राम पंचायत निर्माण रिटैनिंग बाल क्ष्वारन पर मु० 6177/- रु की धनगणि के गवन/छलहरण करने की दोषी पाये गए हैं।

उपरोक्त वर्णित आरोपों में प्रधान की प्रारम्भिक छानबीन के आधार पर संलिप्तता पाए जाने के कारण दिनांक 21-9-1999 को उपायुक्त, सोलन द्वारा प्रधान पद से निलम्बित किया गया था। उपरोक्त श्रीमती सुन्दरी देवी, प्रधान ग्राम पंचायत पोले दा खाला न हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम, 1994 की धारा 148 क अन्तर्गत अपन निलम्बन आदेशों के विरुद्ध अपीली प्राधिकारी के सम्मुख अपील दाखर की थी जिन द्वारा नियमित जांच के आदेश

करते हुए अधीन का निष्पादन किया था। अतः सरकार ने मामले में सच्चाई जानने हेतु धारा 146 के तहत नियमित जांच करवाने का अनुरोध में निर्णय लिया गया है।

अतः हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, उन शक्तियों के अधीन जो कि उन्हें हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम, 1994 की धारा 146 के अंतर्गत प्रदान है, का प्रयोग करते हुए श्रीमती सुन्दरी देवी, प्रधान ग्राम पंचायत पोले दाखाला, विकास खण्ड नालागढ़ जिला सोलन के विरुद्ध लगाए गए आरोपों की जांच हेतु उपमण्डलाधिकारी (नॉ०), नालागढ़ को जांच अधिकारी तथा पंचायत निरीक्षक विकास खण्ड नालागढ़ को प्रस्तुतकर्ता अधिकारी नियुक्त करने के सहर्ष आदेश प्रदान करते हैं। पंचायत निरीक्षक ग्राम पंचायत का रिकार्ड प्रस्तुत करने का साथ-साथ सरकार का पक्ष भी रखेंगे। प्रधान, श्रीमती सुन्दरी देवी, को यह भी निर्देश दिए जाते हैं कि वे जांच के दौरान जांच अधिकारी को सम्मुख उपस्थिति देकर अपना पक्ष प्रस्तुत करें।

शिमला-171009, 5 जनवरी, 2000

संख्या पी 0 तो 0 ए 0 एच 0 ए 0 (5) 25/93-जयपिठिमाता-152-58--यह कि श्री मोहिन्द्र सिंह, प्रधान (नि०), ग्राम पंचायत जयपिठिमाता, विकास खण्ड जुबल-कोटबाई, जिला शिमला को उपायुक्त शिमला द्वारा कार्यालय आदेश सं 0 पी सी 0 एच 0 ए 0 एम 0 एल 0 (10)-216/82 दिनांक 16 मार्च, 1999 अनुसार प्रधान पद के कर्त्तव्य व दायित्व को रोक रंग में न निमाने व सरकारी धनराशि के दुरुपयोग के कारण प्रधान पद से निलम्बित किया गया था किन पर राज्य सरकार द्वारा हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम, 1994 की धारा 146 के अंतर्गत नियमित जांच कराई गई। नियमित जांच में उक्त प्रधान के विरुद्ध निम्नलिखित आरोप सत्य सिद्ध होते हैं :-

1. गांव कलौथा में पशु-तालाब का निर्माण --

यह कि पशु तालाब के निर्माण हेतु वर्ष 1994-95 में मु० 20,000/- रु० स्वीकृत हुए थे जिसका कार्य ग्राम पंचायत द्वारा माह जून, 1995 में पूर्ण करवाया गया तथा इस कार्य का मूल्यांकन मु० 22, 174/- रु० आंका गया है परन्तु मौका-निरीक्षण करने पर निर्माण कार्य विभागीय मापदण्डों के अनुसार नहीं किया पाया गया। अतः जाहिर है कि उक्त प्रधान द्वारा मु० 20,000/- रु० का दुरुपयोग किया गया है।

2. देवता मन्दिर और सराय भवन का निर्माण :

यह कि गांव कलौथा में देवता मन्दिर और सराय भवन निर्माण हेतु मु० 1,70,000 रुपये की राशि स्वीकृत हुई थी जिसमें से प्रधान को मु० 95000/- रु० उक्त कार्य हेतु जारी किए गए थे। दिनांक 12-2-1999 को दो मंजिला भवन के धरातल में सराय व पहली मंजिल में देवता मन्दिर बनाया गया। श्री मोहिन्द्र सिंह प्रधान (नि०) द्वारा उपरोक्त दोनों कार्य बिना विभागीय प्राक्कलन व ड्राइंग के बनाए गए हैं क्योंकि विभागीय मापदण्डों के अनुसार सराय का आकार 18×14 होना चाहिए जबकि किण्ठ अभियन्ता की रिपोर्ट अनुसार दोनों कमरों का आकार 9.35×9.35 है। अतः जाहिर है कि उक्त प्रधान द्वारा उपरोक्त भवन का कार्य बिना प्राक्कलन व ड्राइंग के किया गया है।

3. सामुदायिक/सराय भवन नैहतार :

यह कि सामुदायिक भवन नैहतार के निर्माण हेतु मु० 60,000/- रु० की धनराशि स्वीकृत हुई थी जिसमें से मु० 52000/- रु० उक्त प्रधान को दो विभिन्न किस्तों में निर्माण हेतु अदा की गई थी। मौका निरीक्षण पर यह पाया गया कि सराय भवन का निर्माण पंचायत घर के साथ सांझा रूप में किया गया है जिसमें पानी का रिसाव होना पाया गया जिसके कारण सराय भवन उपयोग के योग्य नहीं पाया गया। स्पष्ट है कि उक्त प्रधान द्वारा मु० 52,000/- रु० का दुरुपयोग किया गया है।

4. अंकेक्षण रिपोर्ट 4/97 से 3/98 में दर्शाई गई अनियमितताएं।

यह कि पंचायत भवन के निर्माण के मस्ट्रोल में मु० 15750/- रु० की अदायगी लेबर को दिखाई गई है तथा निलम्बित प्रधान द्वारा प्रमाणित है परन्तु किसी भी मिस्त्री/बेलदार द्वारा प्राप्ति के हस्ताक्षर नहीं है। इसी प्रकार सीमेंट के क्रय हेतु मु० 1250/- रु० की अदायगी दर्शाई गई है और उक्त प्रधान द्वारा सत्यापित है परन्तु इस पर न तो प्राप्तकर्ता का नाम है और न ही हस्ताक्षर। अतः उपरोक्त के दृष्टिगत पंचायत भवन के निर्माण के मु० 1250/-1575/-17,000/- रु० के संदिग्धपूर्ण वाऊचर तैयार करने का आरोप सत्यसिद्ध होता है।

अतः हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम, 1994 की धारा 146 के अन्तर्गत उपरोक्त श्री मोहिन्द्र सिंह, प्रधान (नि०) ग्राम पंचायत जयपिहिमाता, विकास खण्ड जुब्बल-कोटखाई, जिला शिमला को यह कारण बताओ नोटिस जारी करते हैं कि क्यों न उन्हें उपरोक्त कृत्य के लिए ग्राम पंचायत के प्रधान पद से निष्काशित किया जाए तथा उन्हें इन प्रावधानों के अन्तर्गत 6 वर्ष की कालावधि के लिए पंचायत के पदाधिकारी के रूप में निर्वाचन के लिए निरहित किया जाए।

उक्त प्रधान श्री मोहिन्द्र सिंह इस कारण बताओ नोटिस का उत्तर 15 दिनों के भीतर-भीतर हर हालत में उपायुक्त, शिमला के माध्यम से अधोहस्ताक्षरी को प्रस्तुत करें अन्यथा उनका विरुद्ध एकतरफा कार्यवाही उक्त अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार अमल में लाई जाएगी।

आदेश द्वारा

हस्ताक्षरित/-
आयुक्त एवं सचिव।